# इकाई 5 : राज्य, राष्ट्र और राष्ट्र–राज्य (STATE,NATION AND NATION–STATE)

**इकाई की रूपरेखा**


5.0 उद्देश्य
5.1 प्रस्तावना
5.2 राज्य
5.2.1 राज्य - एक भौगोलिक इकाई
5.2.2 राज्यों का विकास
5.2.3 राज्यों की विशेषताऐं
5.2.4 राज्य के तत्व
5.2.5 राज्यों का वर्गीकरण
5.3 राष्ट्र
5.3.1 राष्ट्र के तत्व
5.4 राष्ट्र - राज्य
5.5 सारांश
5.6 शब्दावली
5.7 संदर्भ ग्रन्थ
5.8 बोध प्रशन के उतर
59 अभ्यासार्थ प्रश्न


## 5.0 उद्देश्य(Objective)

राजनीतिक भूगोल के अन्तर्गत राजनीतिक भूगोलवेत्तओं ने राज्य को एक जीवित इकाई के रूप में प्रतिपादित किया, जो उपयुक्त भौगोलिक वातावरण की प्राप्ति होने पर अपने क्षेत्र का विस्तार करता रहता है और;' अन्ततः वह एक शक्तिशाली राज्य के रूम, में विकसित हो जाता है । राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के अन्तर्गत राज्य का स्थान सर्वोच्च है! । ज्यों–ज्यों राज्य में निवास करने वाले लोगों में परिपक्वता आती जाती है, वैसे–वैसे उनकी राज्यः। के प्रति राजनीतिक आस्था में वृद्धि होती जाती है, इसी के द्वारा राष्ट्र का निर्माण प्रारम्भ हो जाता है । जब लोगों द्वारा अपनी सरकार को महत्व देना प्रारम्म कर दिया जाता है, जो स्वयं उनके लोगों द्वारा परिचालित हो, तब राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने स्वयं को उस राज्य का एक अंग ' मानने में गौरव का अनुभव करता है, तब राष्ट्र–राज्य का विकास प्रारम्भ होता है ।

इस इकाई के अन्तर्गत राज्य, राष्ट्र और राष्ट्र–राज्य की विशद विवेचना प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप समझ सकेंगे कि –

राजनीतिक भूगोल के अन्तर्गत राज्य क्या है, राज्य का विकास कैसे होता है?

- राज्य की विशेषताऐं क्या होती हैं तथा इसके अंग और इकाईयाँ कौन–कौन सी हैं?
- राज्य की संरचना तथा संगठन किस प्रकार का होता है?
- राज्य एवं राष्ट्र में क्या अन्तर है?
- राष्ट्र किसे कहा जाता है तथा इसका उद्भव एवं विकास किस प्रकार होता हैं?
- राष्ट्र के विकास में कौनसे तत्व सहायक होते हैं?
- राष्ट्र–राज्यों का उद्भव किस प्रकार होता है?

## 5.1 प्रस्तावना (Introduction)

ऐतिहासिकता का अध्ययन राजनीतिक भूगोल में अपना विशेष महत्व रखता है,। जिसे हार्टशोर्न, व्हिटलसी, जोन्स आदि विचारकों द्वारा स्वीकार भी किया गया है । इसके. द्वारा भूतकाल की समस्याओं का अध्ययन कर न केवल उनसे परिचित हुआ जाता है, अपितु वर्तमान समस्याओं के समाधान का कार्य भी सुगम हो जाता है । किसी भी राज्य का केन्द्रीय स्थल से क्रमिक विकास, सीमान्त प्रदेशों पर आक्रमण और अधिकार तथा उपनिवेश का विस्तार आदि कई तथ्यों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही समझा जा सकता है । अनेक विद्वानों का विचार है कि राजनीतिक भूगोल में राज्य की संरचना का अध्ययन ही प्रमुखता –रखता है । सभी -राज्यों में राजधानियाँ एवं उद्भव क्षेत्र, सीमायें, प्रान्तीय भाग, सघन एवं कम बसे हुए भाग होते हैं, जिनका तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है । राज्य के प्रारूप से आश्य है कि राजनीतिक इकाईयों का गठन जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हो सकता है, जिसे स्थिति, आकार एवं विस्तार के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है । मुख्य रूप से राज्य के क्षेत्रीय अंगों, जैसे– जनसंख्या, सीमायें, राजधानी. आर्थिक क्षेत्र आदि के लिए संरचना शब्द का प्रयोग होता है । इस प्रकार से व्याख्या करने पर राज्य के स्वरूप की जानकारी प्राप्त हो जाती है, तथा विश्व की विभिन्न राजनीतिक इकाइयों का तुलनात्मक अध्ययन भी सरल हो जाता है ।

एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका के कुछ भागों में राज्य अथवा साम्राज्य का स्वरूप वर्तमान राजनीतिक विकास की चेतना से पूर्व विद्यमान था । प्रारम्भ से ही राज्य को शक्ति पुंज के रूप में देखा एवं इसे लोक कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है । वर्तमान में विश्व में जितने भी स्वतंत्र राज्य विद्यमान हैं, वे क्षेत्रफल, आकृति, आकार, जनसंख्या तथा शासन के प्रकारों के दृष्टिकोण से अत्यधिक भिन्नता लिये हुए हैं । वर्तमान में भी कुछ अवलम्बित राज्य विद्यमान हैं, जिनकी संख्या निरन्तर कम होती जा रही है तथा ऐसे स्वतंत्र राज्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो स्वशासित प्रभुसत्तापूर्ण हैं । प्राचीनकाल में जब विश्व में राज्य जनता का नहीं था और शासन व्यवस्था राजाओं अथवा निरंकुश सत्ताधारियों के पास थी, तब भी अपना जीवन स्तर सुधारने का माध्यम लोगों ने राज्य को ही स्वीकार किया था, और

जब आज लोगों के स्वयं के हाथ में प्रभुसत्ता है, तो भी लोग राज्य को ही अपना जीवन–स्तर सुदृढ़ करने का माध्यम बनाये. हुए है । प्रारम्भ से ही राज्य सभ्य मानव समाज का आवश्यक गुण रहा है. जिसे सभी ऐतिहासिक युगों में समस्त समुदायों द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है । कुछ विद्वान राज्य को नैतिक संस्था तो कुछ संगठित लोक समाज मानते है, कुछ अन्य लोग इसे राष्ट्र और समाज से अलग नहीं मानते हैं ।

राष्ट्र के विचार की भावना के माध्यम से एकत्व का विकास होता है । राज्य का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक होता है न कि धर्म, भाषा अथवा अन्य सामाजिक विशिष्टताओं के विकास क साधन मात्र । जैसे–जैसे किसी राज्य के लोगों में परिपक्वता आती जाती है, उनकी उस राज्य के लिए राजनीतिक आस्था में वृद्धि होती जाती है । सामान्य रूप से किसी राज्य के लोग उस सरकार को ही महत्व देते हैं जो कि उनके स्वयं के लोगों द्वारा ही संचालित हो, विदेशियों के द्वारा नहीं । इस प्रकार उस राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने आपको उस राज्य का अंग मानने में गौरव का अनुभव करता है । प्रारम्भ से ही प्रजा औपनिवेशिक शासन के ,अन्तर्गत हमेशा असंतुष्ट रही और अन्ततः अधिकांश स्थानों पर इस प्रकार की शासन व्यवस्था का अन्त हुआ तथा स्वतंत्र–राष्ट्र–राज्यों (nation– state) का निर्माण हुआ । धर्म एवं भाषा की विविधता होते हुए भी राष्ट्रीयता के विकसित होने पर राजनीतिक समानता का विकास होता है ।

## 5.2 राज्य (STATE)

यदि हम विश्व के मानचित्र को देखें तो यह बात स्पष्ट रूप से दिखायी देती है कि विश्व का पूरा धरातल और सभी मानव राजनीतिक इकाई से सम्बन्धित हैं, जिन्हें वर्तमान में राज्य' के नाम से सम्बोधित किया जाता है । राज्य को विश्व के सभी लोगों ने व्यावहारिक रूप में शासन करने वाली एक इकाई के रूप में स्वीकार किया है । वर्तमान में विश्व में स्थित विभिन्न राज्यों के भौगोलिक एवं राजनीतिक स्वरूप में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है । भिन्न–भिन्न राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे– स्थिति, विस्तार, धरातल, जलवायु, वनस्पति, मिट्टियाँ, कृषि फसलें, खनिज, उद्योग, परिवहन आदि प्रशासनिक स्थिति, सैनिक एवं सांस्कृतिक स्थिति आदि में भिन्नता देखने को मिलती है । किसी भी राज्य के विकास एवं शक्ति को भिन्नता नियंत्रित एवं संचालित करती है । यही कारण है कि राज्य के भौगोलिक–राजनीतिक स्वरूप का राजनीतिक भूगोल के अन्तर्गत अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा ही पूरे या प्रदेशों का अध्ययन किया जाना संभव है ।

### 5.2.1 **राज्य–एक भौगोलिक इकाई** (State -A Geographic Unit)

राजनीतिक भूगोल के अध्ययन की राज्य एक महत्वपूर्ण इकाई है) इसीलिए इसके स्वरूप की पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है । अंग्रेजी के State शब्द का अनुवाद 'राज्य' है, जो ट्यूटोनिक भाषा के State शब्द से आया है । विश्व के भिन्न–भिन्न भागों के विभिन्न विषयों के विद्वानों ने राज्य' को परिभाषित किया है, जिसमें राजनीतिशास्त्र के विद्वानों की संख्या अधिक है, जो कि हमारे अध्ययन क्षेत्र का भाग नहीं है । 'राज्य' को अधिकांश। भूगोलवेत्ताओं ने एक भौगोलिक इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है तथा 'राज्य' के विविध भौगोलिक पक्षों की राजनीतिक भूगोल के अन्तर्गत विशद् व्याख्या प्रस्तुत की है ।

मूडी के अनुसार 'राज्य क्षेत्र व लोगों से मिलकर बनता है जो राजनीतिक स्तर पर एक संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बँधे होते हैं ।" (State is composed of territory and people bound together by organization on a political level".Moodie

इसी प्रकार पाउण्ड्स के अनुसार 'राज्य वहाँ के लोगों द्वारा ढंग से संगठित किया गया एक राजनीतिक क्षेत्र है, जिसकी स्वयं की सरकार होती है और उसके क्षेत्र पर उसका प्रभावशाली नियंत्रण होता है ।The State in area organised politically in an effective manner by an indigeous people with a government in effective control of the era'' Pounds.)

कार्लसन का विचार है कि 'राज्य का क्षेत्र ग्लोब का वह भाग है, जिसकी सीमा में उसकी सर्वोच्च सता होती है, तथा वहाँ के लोगों एवं संसाधनों पर शासन होता है ।" (The territory of a State is that portion of the globe within the bounds of which it exercises supreme authority administering the people and resources therein." Carlson).

उपर्युक्त विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पृथ्वीतल का 'राज्य' एक अभिन्न अंग है, जिसका अपना स्वयं का क्षेत्र होता है, आकार चाहे लघु, मध्यम अथवा वृहत् हो । साथ ही राजनीतिक सता का होना भी राज्य के लिए आवश्यक है । राज्य प्रशासन के रूप में इसका स्वरूप होता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य' के लोगों के हितों की रक्षा करना तथा वही स्थित सभी प्रकार के संसाधनों का नियोजित रूप से उपयोग करना होता है । स्पष्ट है कि राज्यों को केवल मात्र क्षेत्र एवं लोगों का समूह ही नहीं मानना. चाहिये बल्कि राज्य का वास्तविक स्वरूप इन दोनों की क्रिया और प्रतिक्रिया में ही निहित है । भौगोलिक वातावरण की विविधता के कारण इनके प्रारूप में भी भिन्नता देखने को मिलती है । इसी कारण के किन्हीं भी दो राज्यों के मध्य समानता नहीं होकर उनके व्यक्तित्व में भिन्नता देखने को मिलती है ।

सारांश रूप में कहा जा सकता है कि भौगोलिक इकाई के रूप में राज्य मे तीन तथ्यों यथा क्षेत्र, मानव एवं राजनीतिक संगठन को सम्मिलित किया जाता है । ये तीनों तथ्य एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होकर प्रत्येक का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता. है । अन्ततः राज्य, का विकास इनके सामूहिक स्वरूप से ही होता है । वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न राज्यों में राजनीतिक एव आर्थिक भिन्नता के लिए भी यही तत्व उत्तरदायी हैं ।

### 5.2.2 **राज्यों का विकास** (Evolution of State)

"रक्त सम्बन्ध अथवा बन्धुता से समाज का निर्माण होता है और अन्ततः समाज से–राज्य का निर्माण होता है ।" (Kinship creates society and society at length creates State R.M.Maciver) मानव का प्रारम्भ से हो यह स्वभाव रहा है कि वह समुदाय अथवा मानव वर्ग के रूप में रहता आया है । इसके माध्यम से वह अपने साथियों से प्रगति तथा कल्याण के लिए भौतिक लाभ की प्राप्ति करता रहा है । समूह में रहने के कारण उसे अधिक सुरक्षा मिली और श्रम का लाभ भी प्राप्त हुआ । शक्ति वर्ग संगठन का आधार रहा है और जैसे–जैसे वे शक्तिशाली होते गये व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होती गयी और शक्ति तथा संगठन का विभाजन अविचारणीय होता गया । शक्तिशाली वर्गो ने हमेशा से ही कम संख्या के कमजोर वर्गो को अपने अधीन बनाया । विभिन्न समुदायों ने एक स्थान पर स्थायी रूप से बसकर कृषि का विकास किया । शनैः शनैः लोगों का भूमि के लिए मोह बढ़ने के साथ, उन्होंने सघन कृषि करना प्रारम्भ किया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव हुई, जिसके कारण कुछ विशिष्ट केन्द्र विकसित हुए तथा इन्हीं केन्द्र स्थलों से राज्य के उद्भव और विकास का सूत्रपात होना माना जाता है ।

ऐसा माना जाता है कि मानव का इतिहास जितना पुराना है, राज्य व्यवस्था भी उतनी ही प्राचीन है । राज्य का स्वरूप जिसे हम वर्तमान में देखते हैं, एक लम्बे विकास का परिणाम है । राज्य के विकास के लिये केवल मात्र सामाजिक या राजनीतिक परिस्थितियाँ ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि भौगोलिक वातावरण का योगदान भी इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है । राज्य विकास प्रक्रिया के आधार पर इसे अधोलिखित तीन कालों में विभक्त किया जा सकता है –

(1) **प्राचीन काल** – इस बात की सही–सही जानकारी उपलब्ध नही है किए कब एवं कहाँ पर राज्य–व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ था, किन्तु इस तथ्य को सभी लोग स्वीकार करते हैं कि राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है । सर्वप्रथम मिश्र में राज्य के वास्तविक स्वरूप की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई ऐतिहासिक तथ्य पुष्टि करते हैं, जिसके पीछे सबसे प्रमुख कारण मिश्र की तीन महाद्वीपों के संदर्भ में स्थित होना । अनेक जातीय एवं सामन्ती लड़ाइयों के बाद मिश्र ने स्थायित्व प्राप्त किया । इसका स्वरूप न केवल सैनिक था, बल्कि दूर क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव था ।

प्रारम्भ में इटली और ग्रीस के 'नगर–राज्यों' का प्रशासनिक दृष्टिकोण से संगठित रूप मैं महत्वपूर्ण स्थान था । हालांकि ये बहुत छोटे थे किन्तु आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली थे उस समय कुछ नगर राज्य तो ऐसे थे जो अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहे, जबकि कुछ अन्य अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जिनमें स्पार्टा, फ्लोरेन्स एथेन्स, पीसा आदि थे। अपने बड़े हुए क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण नहीं कर पाना बाद में इन नगर–राज्यों के पतन का प्रमुख कारण रहा । जब रोम के नगर–राज्यों ने इटली के नगर–राज्यों को ईसा से 350 वर्ष पूर्व जब जीतना प्रारम्म किया तब पश्चिमी जगत में रोमन साम्राज्य का उद्भव हुआ । इसके बाद एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना रोमन साम्राज्य के अधीन की गयी । प्रो. मूडी के अनुसार रोमन साम्राज्य की व्यवस्था प्रथम विशाल राजनीतिक राज्य के रूप में थी जिसमें राज्य के 'तीनों तत्व–मानव, क्षेत्र और संगठन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। रोमन साम्राज्य में न केवल कानून व्यवस्था सुदृढ़ और सफल थी. बल्कि उन्होंने सबसे पहले सड़कों का महत्व प्रशासन के सफल संचालन के लिए समझा और इस बात के प्रयास किये कि । साम्राज्य के विभिन्न भागों को सभी सड़कें रोम से जोड़े ।

(2) **मध्यकाल** – ईसा के बाद चौथी शताब्दी में रोमन साम्राज्य' का अन्त हो गया तथा उसके पश्चात् यूरोप में जिस प्रकार का अंधकारपूर्ण एवं अराजक वातावरण बना उस काल को इतिहास में अंधयुग (Dark Age) के नाम से पुकारा जाता है । इस प्रकार की परिस्थितियों में धीरे–धीरे सामन्तवादी व्यवस्था का उद्भव हुआ । शासन, आर्थिक क्रिया–कलाप एवं जीवन को सामान्य रूप से इस व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत कर दिया था, जिसमें सबसे निचले स्तर पर भूमिहर था । चर्च का प्रभाव उस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण था । अत: इस काल में निम्न एवं मध्यम वर्ग में ऐसी दमनकारी व्यवस्था के कारण विद्रोही भावनाओं ने जन्म लेना प्रारम्म कर दिया । इस काल में यूरोप विशेषरूप से चौदहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक– विश्व की विभिन्न घटनाओं का केन्द्रीय रंगमंच रहा । इंग्लैण्ड, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि कुछ राज्य 1500 ई. तक यूरोप की सीमा में विकसित हुए ।

(3) **आधुनिक काल** – राज्यों का शासन एवं शक्ति का उपरोक्त कालों में केन्द्रीयकरण व्यक्ति में रहा, किन्तु वर्तमान राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत संसदीय सरकारों का निर्माण हुआ तथा स्वायत्त शासन का विस्तार हुआ । प्रो. मूडी के अनुसार आधुनिक काल का राजनीतिक इतिहास एक व्यक्ति अथवा सुविधा सम्पन्न कुछ व्यक्तियों के प्रभुत्व को सफलतापूर्वक कुचलने की कहानी है, जिसके फलस्वरूप संसदीय सरकार का विकास हुआ तथा शासन का विस्तार हुआ । (The political history of the Modern Age is largely the story of the successful struggle to wrest this omnicompetence from an individual or from a privileged

few and ,through the growth of Parliamentary Government and the extension of the franchise , to bestow self -government–'Moodie.)

उक्त विचारों का अर्थ यह नहीं है कि राज्यों के विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, बल्कि यह प्रक्रिया अब भी जारी है । अनेक तत्वों जैसे प्रतिनिधि सरकार, औद्योगिक क्रान्ति, जनसंख्या परिवर्तन, राज्यों की आपसी निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास आदि ने वर्तमान राज्यों के विकास पर प्रभाव डाला है । यही कारण है कि जो राज्य व्यवस्था प्रथम महायुद्ध से पूर्व केवल यूरोप तक सीमित थी, वह विश्वव्यापी हो गयी ।।

### 5.2.3 **राज्यों की विशेषताऐं –**

वर्तमान में राज्यों की विकास प्रक्रिया के जारी रहने के साथ–साथ उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताऐं भी हैं । राज्य की सम्प्रभुता वर्तमान राज्य की सर्वप्रथम एवं मूलभूत विशेषता है, जिसके अन्तर्गत राज्य का अपनी सीमा में आने वाले सभी क्षेत्रों एवं निवासियों पर नियंत्रण रहता है । राज्यों द्वारा आन्तरिक शासन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो का परिचालन इसी के माध्यम से किया जाता है ।

राष्ट्रवाद का सिद्धान्त राज्यों की द्वितीय महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक गुण के रूप में माना जा सकता है, जिसके माध्यम से राज्य एकता के सूत्र मे बंधे रहते हैं । तीसरी मुख्य विशेषता राज्य के लिए राष्ट्रीय शक्ति है, जिसके माध्यम से राज्य को कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान की जाती है । उपरोक्त राजनीतिक विशेषताओं के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न भौगोलिक कारक भी राज्य को विशिष्टता 'प्रदान करते हैं ।

राजनीति विज्ञान में राज्यों के विकास के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्तों एवं संकल्पनाओं का वर्णन किया गया है, जैसे दैवी सिद्धान्त, शक्ति सिद्धान्त, सामाजिक अनुबंध सिद्धान्त, आनुवंशिक ' सिद्धान्त, विकासवादी सिद्धान्त आदि । राज्य को ईश्वरीय देन दैवी सिद्धान्त के अन्तर्गत माना है जबकि शक्ति सिद्धान्त के अनुसार जो समुदाय अथवा व्यक्ति शक्तिशाली होगा वही राज्य का शासक और निर्माता होगा । सत्रहवीं एवं अठारहवीं शताब्दी में हॉब्स, लॉक, रूसों जैसे विद्वानों ने सामाजिक अनुबंध सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार मानव एक सामाजिक प्राणी है तथा राज्य की उत्पति सामाजिक मान्यताओं और परस्पर सहयोग से होती है । आनुवांशिक सिद्धान्त के अन्तर्गत राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम माना जाता है, किन्तु सता मातृ एवं पितृ में विश्वास करते हैं । विकासवादी सिद्धान्त का 'मूल यह है कि वास्तव में राज्य का विकास क्रमिक दीर्घकालीन प्रक्रिया से हुआ है । भौगोलिक पर्यावरण की इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

### 5.2.4 **राज्य के तत्व** (Elements of the States)

राज्य के आवश्यक तत्वों के अन्तर्गत मूडी ने क्षेत्र, वहाँ के लोग और राजनीतिक संगठन को सम्मिलित किया है । राज्य के तत्वों को अध्ययन के दृष्टिकोण से निम्न वर्गो में विभक्त किया जा सकता है, जिनके आधार पर राज्य की संरचना को विस्तार से समझा जा सकता है – (1) राज्य के लोग या जनसंख्या (2) राज्य का भू–भाग अथवा निर्धारित क्षेत्र (3) राज्य की सरकार(4) राज्य की प्रभुसता (5) राज्य का आर्थिक स्वरूप रुद्ध संचार एवं परिवहन व्यवस्था ।

(1) **राज्य के लोग या जनसंख्या** – किसी भू–भाग में निवासित लोगों के बिना राज्य की कल्पना असंभव है । किसी राज्य में कितनी संख्या को आदर्श जनसंख्या के रूप मैं स्वीकार किया जाये यह एक कठिन कार्य है । किन्तु राज्य में उसके भू–भाग के आकार, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता आदि के आधार पर आदर्श अथवा अनुकूलतम जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है । जनसंख्या का राज्य के राजनीतिक भौगोलिक प्रारूप के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान है । राज्य को वहाँ की जनसंख्या का आकार, प्रकार, वितरण आदि विभिन्न प्रकार से प्रभारित करते हैं । 'राज्य की प्रगति तभी होती है, जब जनसंख्या एवं संसाधनों में संतुलन एवं सामजस्य होता है । यदि इनमें संतुलन की स्थिति नहीं होती है तब अनेक प्रकार की समस्याऐं जन्म लेती हैं तथा राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । वर्तमान में भोग अनेक ऐसे राज्य है, जो जनसंख्या की अधिकता के कारण जनाधिक्य की समस्या का सामना कर रहे हैं और इस धारण वे प्रगति नहीं कर पाते । दूसरी ओर कई राज्यों में जनसंख्या शक्ति का प्रतीक तथा उत्पादन क्षमता की द्योतक होती है, उदाहरणार्थ– जापान । वर्तमान में राज्य शक्ति के रूप में जनसंख्या के गठन पर अधिक बल दिया जाता है. जबकि जनसंख्या को संख्यात्मक दृष्टि से महत्वहीन माना जाता है । राष्ट्रहित के लिए किसी राज्य को सम्पूर्ण जनता का एकजुट होना उत्तम माना जाता है । प्रथम विश्व युद्ध के बाद कम जनसंख्या ताले कुछ राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया किन्तु वर्तमान में कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश राज्य जनसंख्या वृद्धि पर रोक के प्रबल समर्थक हैं तथा इस हेतु गंभीर प्रयास भी कर रहे हैं । किन्तु अब भविष्य के सबल राज्यों के रूप में शिक्षा, तकनीकी और कुशल जनसंख्या के बाहुल्य वाले राज्यों को माना जाता है ।

वर्तमान में राज्यों के संसाधनों, उद्योगों एवं कृषि भूमि की क्षमता के आधार पर आदर्श जनसंख्या के रूप में आका जाता है ।

(2) **राज्य का भू–भाग अथवा निर्धारित क्षेत्र** – किसी राज्य। में भूभाग के अभाव में प्रभुत्व सामन्त राज्य की कल्पना करना भी व्यर्थ है । प्राचीन काल में एक: ऐसा युग था जब नगर–राज्य या कबिलाई राज्य आदर्श राज्य के रूप में माने जाते थे, जिनका क्षेत्रफल बहुत कम हुआ करता था और वहां –के– शासकों और सभी निवासियों को अपने राज्य की सीमाओं का ध्यान रहता था, किन्तु वर्तमान में

नगर–राज्य की कल्पना असंभव है । राज्य का भूभाग उसे विविध सम्पदा उपलब्ध कराता है तथा आधुनिक राज्य की प्राथमिक आवश्यकता वहाँ की प्राकृतिक सम्पदा अजंता संसाधनों की विविधता है । विस्तृत राज्य क्षेत्र के अभाव में शक्तिशाली राज्य की कल्पना करना कठिन है, क्योंकि किसी भी शक्तिशाली राज्य के लिये अतुल्य प्राकृतिक सम्पदा अथवा संसाधनों फी जरूरत उनकी प्राप्ति एवं उनकी उपलब्धता वरदान ' है । उदाहरण के रूप में रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, आस्ट्रेलिया आदि राज्य अपने विशाल आकार एवं भूभाग के –कारण प्राकृतिक सम्पदा में धनी हैं एव लगातार विकास के पथ पर अग्रसर हैं, यद्यपि इन राज्यों के सम्पूर्ण क्षेत्र में अभी भी यातायात एवं परिवहन की सुविधाओं का समान रूप से विकास नही हो पाया है । राज्य के भूभाग अथवा क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं में मुख्य रूप से स्थिति, आकार, विस्तार, धरातल जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियाँ, जल संसाधन, खनिज संसाधन आदि को सम्मिलित किया जाता है । साथ ही किसी राज्य के भूभाग अथवा क्षेत्र का निर्धारण उसकी सीमाओं के द्वारा किया जाता है, इसलिए सीमाओं की प्रकृति, प्रकार, विकास को भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है ।

(3) **राज्य की सरकार** – राज्य की सरकार अथवा प्रशासन का स्वरूप क्या हो यद्यपि यह विषय राजनीति विज्ञान से सम्बंधित है, किंतु राजनीतिक भूगोल के अन्तर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि उस क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण एवं नियंत्रण का स्तर, आंतरिक संगठन का प्रकार एवं उसकी प्रभावशीलता किस प्रकार की है । राज्य की जनसंख्या एवं भूभाग के समान ही सरकार भी राज्य का एक आवश्यक तत्व है । राज्य अथवा राजनीतिक सता का अस्तित्व इसके अभाव में कभी नहीं रहा है । राज्य के संकल्पों का निर्माण, उनकी अभिव्यक्ति तथा पूर्ति सरकार के माध्यम से ही साकार रूप लेते हैं । राज्य शक्ति का निर्णायक तत्व सरकार की होती है और शक्ति निर्माण ही संगठन का सबसे बड़ा कार्य भी है । शासक एवं प्रजा राज्य के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं । जनता के लिए जन हितार्थ निर्णय लेना राज्य के लिए आवश्यक होता है, ओर इस प्रकार के निर्णय तब ही लिये जा सकते है' जब राज्य में सरकार हो । भिन्न– भिन्न राज्यों में नीति निर्धारण व निर्णय करने का कार्य एक समूह द्वारा राज्य नीति के पालन हेतु किया जाता है, जिसका स्वरूप भिन्न–भिन्न होता है । दूसरी ओर अभी भी विश्व के कई राज्य स्वतंत्र होते हुए भी अन्य राज्यों पर निर्भर है ।

(4) **राज्य की प्रभुसत्ता** – आधुनिक राज्य का सर्वाधिक –महत्वपूर्ण तत्व प्रभुसत्ता है. जिसके कारण वह अन्य राज्यों, समुदायों व समूहों से पृथक बना रहता है । मूडी के शब्दों में ' 'आधुनिक राज्य सम्प्रभुत्व सम्पन्न राज्य होता है, यानी उसका अपने सीमा क्षेत्र में व लोगों पर कुछ गौण अपवादों को छोड़कर पूरा प्रभुत्व होता है और इस दृष्टि से वह किसी अन्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी नही होता है, अर्थात् राज्य राजनीतिक दृष्टि

से पूर्ण रुपेण स्वतंत्र, होता है । " राज्य सता के अधीन राज्य के आन्तरिक व बाह्य सम्बन्धों को निर्देशित व नियंत्रित करने का पूर्ण अधिकार होता है । अत: राज्य में कोई विरोधी या समानान्तर सता आन्तरिक रूप से राज्य में नहीं होनी चाहिये गया राज्य विदेशी नियंत्रण, आदेश अथवा प्रभाव से बाह्य रूप से पूर्णत: मुक्त रहना चाहिए । अधिकांश राज्यों ने प्रभुसत्ता प्राप्ति हेतु वर्षो तक कड़ा संघर्ष किया है और इसे प्राप्त करने वाले देशों की संख्या लगातार अधिक होती जा रही है ।

(5) **राज्य का आर्थिक स्वरूप** – किसी राज्य की सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति का निर्धारण उसकी आर्थिक क्षमता के आधार पर होता है । आर्थिक संसाधन एवं अर्थव्यवस्था राज्य की आय का प्रमुख स्त्रोत होते हैं । इनके अन्तर्गत कृषि भूमि, उसका प्रकार, स्वरूप, कृषि उत्पादन, खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग, औद्योगिक उत्पादन, व्यापार आदि को सम्मिलित किया जाता है । सभी राज्यों में एक ऐसा क्षेत्र होता है, जहाँ पर अनेक आर्थिक क्रिया–कलापों का केन्द्रीयकरण हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों को उस राज्य का 'आर्थिक केन्द्र स्थल' (Ecumene) के नाम से जाना जाता है, जहाँ परिवहन के साधनों का भी केन्द्रीकरण हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों की सामरिक एवं –राजनीतिक महता सभी राज्यों के लिए अत्यधिक होती है, उदाहरणार्थ– संयुक्त राज्य अमेरिका का उतरी–पूर्वी क्षेत्र, जर्मनी का राइन, अर्जेन्टाइना का पम्पा क्षेत्र आदि ।

(6) संचार एवं परिवहन व्यवस्था – संचार एवं परिवहन के साधन भी राज्यों के महत्वपूर्ण तत्वों के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाते हैं, जिनके माध्यम से राज्य के विभिन्न भागों में मनुष्यों एवं उनके विचारों का आदान–प्रदान संभव होता है । राज्य के शासन में प्रभावशीलता परिवहन के साधनों के माध्यम से आती है और इससे सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मदद मिलती है ।

### 5.2.5 **राज्यों का वर्गीकरण** (Classification of State)

अनेक विद्वानों ने राज्यों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न आधारों को काम में लिया हैं । जिनमें राज्य की विकास अवस्था, आकृतिमूलक, आचरण, शक्ति सूचकांक, दलबंदी आदि आधार महत्वपूर्ण हैं । क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के तथ्यों का प्रयोग आकार के आधार पर वर्गीकरण हेतु किया गया है । राज्यों की भौगोलिक एवं राजनीतिक विविधता के कारण उनका वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है । इस प्रकार अनेक आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया गया है, जिनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है –

(1) **राजनीतिक आधार पर राज्यों का वर्गीकरण** – राज्यों को वहाँ पर प्रचलित शासन व्यवस्था के आधार पर निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है –

1. राजनीति और धर्म के सम्बन्ध के आधार पर धर्म आधारित राज्य तथा धर्म निरपेक्ष राज्य ।

2. शासन करने वाले शासकों को संख्या के आधार पर राजतंत्र, तानाशाही अथवा प्रजातंत्र । प्रजातंत्र का प्रारूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है ।
3. राज्यों को कार्यपालिका और विधानसभा के सम्बन्धों के आधार पर संसदीय अथवा अध्यात्मक श्रेणियों में बांटा जाता है ।
4. राज्यों को शासन के विभाजन के आधार पर एकात्मक या संघीय राज्यों में बांटा जाता है ।

(2) भौगोलिक स्थिति. विस्तार और आकार के आधार पर वर्गीकरण –

स्थिति के आधार पर राज्यों को मुख्य रूप से सामुद्रिक एवं महाद्वीपीय श्रेणियों में बांटा जा सकता है । सामुद्रिक स्थिति वाले राज्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे – एक सागरीय, द्विसागरीय, तीन सागरीय, बहुसागरीय आदि । चारों ओर स्थल से घिरे राज्यों को महाद्वीपीय राज्यों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है, जैसे स्विटजरलैण्ड, बोलीविया आदि ।

राज्यों को क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर पाँच भागों में बांटा जा सकता– है–

1. अति वृहत् राज्य जैसे– रूस, कनाडा आदि,
2. वृहत् राज्य जैसे – फ्रांस, मेक्सिको आदि,
3. मध्यम आकार के राज्य जैसे – ग्रेट ब्रिटेन, पौलेण्ड आदि,
4. छोटे राज्य जैसे – नीदरलैण्ड, श्रीलंका आदि,
5. अति छोटे राज्य जैसे – इजराइल, कम्बोडिया आदि ।

आकार के आधार पर राज्य निम्न रूप में हो सकते हैं –

1. लम्बाकार राज्य जैसे – चिली. इटली, नार्वे आदि,
2. संयुक्ताकार राज्य जैसे – हंगरी, बेल्जियम, पौलेण्ड आदि,
3. विस्फोटाकार राज्य जैसे – बर्मा, थाइलैण्ड आदि,
4. विच्छिन्नाकार राज्य जैसे – जापान, इण्डोनेशिया. फिलिपाइन्स आदि,
5. भेदनाकार राज्य जैसे – बसूतोलैण्ड का दक्षिण अफ्रीका में स्थित होना ।

(3) **फाल्केनबर्ग के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण** –

राजनीतिक भूगोल में फाल्केनबर्ग ने सर्वप्रथम, 'चक्र परिकल्पना' ब्लबसम ब्वदबमचजद्ध को लागू किया, जिसे डेविस ने स्थलाकृतियों के विकास के लिए काम में लिया। था । उन्होंने राज्य की विकास के आधार पर तीन अवस्थायें युवा, प्रौढ़ एवं वृद्यावस्था बताई –

(i) **युवावस्था** (Youth) – उनके अनुसार सम्प्रभुता प्राप्त करने के पश्चात् एक नवीन उद्भूत राज्य सर्वप्रथम आन्तरिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाकर उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है । इस अवस्था मैं राज्य का ध्यान क्षेत्रीय विस्तार की ओर नहीं होता है । 1776 से 1803 के संयुक्त राज्य अमेरिका के काल को फाल्केनबर्ग

ने युवावस्था के रूप में रेखांकित किया है । इसके पश्चात् राज्य क्षेत्रीय विस्तार की ओर ध्यान केन्द्रित करता है ।

(ii) प्रौढ़ावस्था (Maturity) – राज्य का प्रयास इस अवस्था में इस बल पर केन्द्रित करता है कि उसके द्वारा किये गये क्षेत्र विस्तार की सुरक्षा की जाये तथा पूर्ण स्थायित्व प्राप्त करने पर विशेष बल दिया जाता है ।

(iii) वृद्धावस्था (Old age) – फाल्केनबर्ग का विचार है कि इस अवस्था में ऐसे राज्य आते हैं, जिनकी शक्ति क्षीण होने लगती है तथा राज्य का आन्तरिक विखण्डन होने लगता हैं ।

राजनीतिक भूगोल में उपरोक्त चक्र परिकल्पना' 1930 में प्रस्तुत की गयी, थी जिसका वर्तमान में अधिक महत्व नहीं है ।

(iv) **गोबलेट के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण** –

'पोलिटिकल ज्योग्राफी एण्ड वर्ल्ड मै' नामक पुस्तक में गोबलेट ने तीन प्रकार के राज्य बताये –(1) सघन राज्य – क्षेत्रीय –साधनों के उपयोग से जिन्हें आर्थिक विकास एवं राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति होती है । (ii) विस्तृत राज्य – अन्य राज्यों पर अधिकार' कर एवं उनके संसाधनों का उपयोग कर इस प्रकार के राज्य शक्तिशाली बन जाते हैं । (iii) मिश्रित राज्य – ऐसे राज्य जो अपने संसाधनों का तो उपयोग करते ही है साथ ही अन्य देशों के संसाधनों का भी यथासंभव उपयोग करते है ।

(v) **राज्यों का शक्ति के आधार पर वर्गीकरण** –

यह एक सापेक्षित तथ्य है, राज्यों की शक्ति के निर्धारण का कार्य बहुत जटिल समस्या है । समय के साथ इसमें परिवर्तन भी आता रहता है । राज्यों की शक्ति का निर्धारण किसी एक तत्व के आधार पर करना कठिन है । जिन तथ्यों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है, उनमें जनसंख्या तथा उसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात, कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत, विद्युत उत्पादन, इस्पात का उत्पादन, सामरिक महत्व के खनिजों का उत्पादन, विदेश व्यापार आदि प्रमुख हैं । इनके आधार पर विश्व के राज्यों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है । प्रथम श्रेणी में शक्तिशाली राज्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका. रूस, चीन आदि । द्वितीय श्रेणी में जर्मनी, फ्रांस' ब्रिटेन, भारत, कनाडा, जापान आदि राज्य तथा तृतीय श्रेणी में राज्यों को जिनमें अधिकांश अफ्रीकी. दक्षिणी अमेरिकी एवं एशियाई राज्य हैं ।

उपरोक्त विभिन्न वर्गीकरणों को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि राज्यों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण अथवा विभाजन पूर्ण नहीं है, क्योंकि राज्यों के भौगोलिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक आदि तत्वों में इतनी अधिक विविधता :। –है कि राज्यों का सर्वमान्य वर्गीकरण संभव नहीं है ।

**बोध प्रश्न** – 1

1. राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं ने राज्य को प्रकार की इकाई के रूप में प्रतिपादित किया

……

2. किन्हीं दो राजनीतिक भूगोल के विद्वानों के नाम लिखिये ।

……

3. अंग्रेजी का 'State' शब्द कौनसी भाषा के ' State' शब्द से आया है ।

…….

4. भौगोलिक इकाई के रूप में राज्य में किन तीन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है ।

…….

5. राज्यों की विकास प्रक्रिया को किन कालों में विभक्त किया जा सकता है ।

……..

6. राज्य के किन्हीं दो तत्व लिखिये ।

…….

## 5.3 राष्ट्र (NATION)

राष्ट्र एवं राज्य शब्दों का उपयोग अनेक बार एक ही अर्थ. थे; रूप में कर लिया जाता है, जबकि वास्तव में यह सही नहीं है, क्योंकि दोनों शब्दों का अलग अर्थ है तथा एक दूसरे से भिन्नता भी है । पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि राज्य के अन्तर्गत क्षेत्र एवं जनसंख्या आती है, जिसको राजनीतिक संगठन आबद्ध करता है ।

राष्ट्र अथवा अंग्रेजी के Nation शब्द की उत्पत्ति वो सम्बन्ध में ऐसा माना जाता है लेटिन भाषा के नेसिया (Natio) से हुई है, जिसका अर्थ 'जन्म अथवा जाति' से है । एक राज्य की सीमाओं तक ही सीमित रहना किसी राष्ट्र के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि राजनैतिक सीमाओं से दूर अन्य क्षेत्रों में भी उसका विस्तार संभव है । अर्थात् राष्ट्र सामान्य सांस्कृतिक विशेषताओं का समूह है, जबकि राज्य को एक राजनीतिक इकाई के रूप में जाना जाता है । मुख्यत. भाषा को राष्ट्र की इन विशेषताओं में प्रो. मूडी ने सर्वाधिक महत्व दिया है । राष्ट्रीय एकता की भावना अधिकांश राज्यों के लोगों में स्वयं होती है । अन्य राज्यों के लोगों से क्षेत्र व सरकार के समान होते हुए भी यही लक्षण उसे भिन्न बनाये रखता है और राष्ट्रीय एकता 'की भावना उन्हें संगठित बनाये रखती है । वर्तमान में आधुनिक राज्यों का विकास राष्ट्रीयता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है । सामाजिक एवं प्राकृतिक विकास के लम्बे काल से राष्ट्रों का विकाश, हुआ है, तथा स्वतंत्र रूप से राजनीतिक व्यवस्था के रूप में राष्ट्रीयता की स्थिति उभर सकी है । मूडी के अनुसार 'राज्य एक राजनीतिक समुदाय है, जबकि राष्ट्र समान भाषा एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों की विशिष्टता लिये हुये होता है। (''The State is a political community whereas the national is characterized by cultural ties most frequentty expressed in the possession of a common language." Moodie).

राष्ट्रवाद के विकास से पूर्व ही 1914 से पहले के अधिकांश राज्यों की वर्तमान सीमाऐं निर्मित हो चुकी थी । अधिकतर यूरोपीय राजनीतिक संगठनों जा स्वरूप राष्ट्रीय था, अर्थात् राज्य के रूप में तो वे विद्यमान थे, किन्तु सर्वत्र राष्ट्रीयता जैसा लक्षण विद्यमान नहीं था । बड़े–बड़े राज्यों के खण्डित होने के पश्चात् राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। राज्य के निर्माण के बाद राष्ट्र का स्वरूप फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, स्विटजरलैण्ड, स्वीडन आदि में उभरा । उसी राष्ट्रीयता की भावना का परिणाम था कि लोग अपने आपको फ्रांसिसी, ब्रिटिश, जर्मन, पोलिश, इतालवी आदि के रूप में कहने अथवा पहचानने लगे । प्रत्येक राज्य को अपना पृथक व स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखने का अधिकार राष्ट्रीयता के उदय से दृष्टिगत होने लगा । पराधीन राज्यों में बीसवीं शताब्दी में राष्ट्रीयता की भावना अधिक तेजी से जागृत हुई जिससे साम्राज्यवादी विचारधारा का विरोध हुआ और राष्ट्रीय स्वाधीनता की विचारधारा का उदय हुआ । राज्यों द्वारा की प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक जनसमूह को अपनी समृद्धि की दिशा में प्रयास करने के अवसर होने लगे ।

विद्वानों में राष्ट्र के निर्धारक तत्वों को लेकर मतैक्य नहीं है । कुछ विद्वानों का विचार है कि भाषा अधिक महत्वपूर्ण है तो कुछ का विचार है कि की महता अधिक है । लान्यी (Lanyi) एवं मेक विलियम्स (McWilliams) ने इसके भौगोलिक को स्पष्ट करते हुए मत व्यक्त किया है कि – 'एक राष्ट्र, एक समान संस्कृति, समान चिन्ह. विश्व के सम्बन्ध में विशिष्ट दृष्टिकोणों से भिन्नता रखता है । एक राष्ट्र को दूसरे संस्कृति समूह। से पृथक करने वाला –तत्व एक क्षेत्र के प्रति लगाव तथा भावना होता है ।

(A Nation implies a common culture ,common symbols a particular view of the world is distinct from other world views.What makes a natonal different from other cultural groups hweever is that one of the symbols associated with its vale and attitudes is a particular piece of territory. -Lanyi & McWilliams).

सांस्कृतिक एकत्व एवं भावना की राष्ट्र में प्रधानता होती ' है । ऐतिहासिक घटनाक्रम एवं समान भावना के परिणामस्वरूप ही राष्ट्र का उद्भव होता है । राष्ट्र के विकास के प्रति राष्ट्रीयता के पोषक तत्व हमेशा तत्पर रहते हैं तथा संकट के समय उनमें " की भावना जागृत होती है । डूयट्ज (Deutsch) ने समय के साथ किस प्रकार राष्ट्रीयता एवं का विकास होता है उसे इस प्रकार रेखात्मक रूप में इंगित किया है

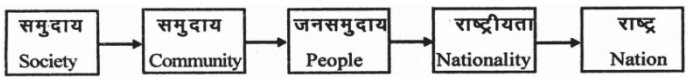


उदाहरणार्थ भारत में अनेक धर्म, भाषा, जाति, आचार–विचार आदि के लोग निवास करते हैं, यद्यपि धर्म एवं भाषा की विविधता राजनीतिक एवं भौगोलिक

दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एकता में बाधक है, किन्तु फिर भी भारतीय संस्कृति में इस विविधता के मध्य एकता है, जो शताब्दियों से यहाँ के धर्मावलम्बियों एवं विविध भाषायी लोगों को एकता के सूत्र में बांधे हुए है । अनेक बार विदेशी सता से संघर्ष के लिये भी राष्ट्रवाद का उद्भव होता है. और जब राष्ट्रीयता मजबूत हो जाती है तो राष्ट्र का विकास होता है । मिनोगू (Mingue ने छः प्रकार की राष्ट्रीयता का वर्णन किया है – (1) राज्य के उद्भव से पूर्व भी राष्ट्रीयता, (2) राज्य के उद्भव के पश्चात् की राष्ट्रीयता, (3) तीसरे विश्व की राष्ट्रीयता, (4) उद्देश्यात्मक राष्ट्रीयता (5) सामुदायिक संघर्ष की राष्ट्रीयता और (6) सम्पूर्ण राष्ट्रीयता ।

सारांश रूप में कहा जा सकता है कि जब कुछ सामान्य तथ्य एक सामाजिक 'समुदाय को संयुक्त करते हैं, उसी समय ही राष्ट्रीयता का जन्म होता है । धर्म, भाषा, राजनीतिक विचारधारा, आचार–विचार, ऐतिहासिक आधार, समान जाति से उत्पति का भाव आदि तत्व राष्ट्रीयता के संयुक्त के रूप में कार्य करते हैं । ये सभी तल सभी स्थानों पर समान रूप से प्रभावशाली नहीं होकर, कुछ तत्व अधिक प्रभावशाली होते हैं । साथ ही भौगोलिक समानता भी एक ऐसा तत्व है, जो राज्यों के लोगों में एकता की भावना उत्पन्न करता है । राष्ट्रवाद को बनाये रखने और उसे विकसित करने में किसी देश की प्राकृतिक सीमायें बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं ।

अतः कहा जा सकता है कि राज्य एवं राष्ट्र समान नहीं होकर भिन्नता रखते हैं तथा इनके अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है–

(1) राष्ट्र की विशेषता सांस्कृतिक सम्मिश्रण है, जबकि राज्य एक राजनीतिक समुदाय के रूप में है ।

(2) राजनीतिक सीमाओं से राज्य का क्षेत्र सीमित तथा आब(रहता है, जबकि राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं है, उसका विस्तार अन्य राज्यों में भी हो सकता है ।

(3) राष्ट्र का सम्बन्ध भावनात्मक होता है, जबकि राज्य एक कानूनी तथ्य है ।

(4) राष्ट्र की एकता का अधार धर्म, भाषा, जाति आदि पर आधारित होता है जबकि राज्य की एकता का सूत्र वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में निहित होता है ।

(5) शासन व्यवस्था राज्य में एक ही प्रकार की होती है, जबकि राष्ट्र के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है. क्योंकि अनेक राज्यों में अनेक राष्ट्रीयता होती है ।

**राष्ट्र के तत्व** (Elements of the Nation)

राष्ट्र के आवश्यक तत्वों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है – (1)–प्रजाति एवं रक्त की एकता, (2) भाषा सम्बन्धी एकता, (3) धर्म सम्बन्धी एकता, (4) भौगोलिक समरूपता, (5) सामान्य आर्थिक सम्बन्ध एवं (6) ऐतिहासिक, सामाजिक–सांस्कृतिक एकता ।

(1) **प्रजाति एवं रक्त की एकता** – प्रजाति एवं रक्त सम्बन्धी एकता की विचारधारा ने राष्ट्रीयता की भावना का मार्गदर्शन किया है, क्योंकि जब एक सामाजिक

वर्ग को कुछ उद्देश्य निष्ठा सीमाओं में परिसीमित कर दिया जाता है तब ही राष्ट्रीयता का आविर्भाव होता है । कोहेन का विचार है कि एक वंश क्रम. भाषा, क्षेत्र, राजनीतिक एकता, धर्म, रीति रिवाज परम्पराऐं और सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रीयता सम्बन्धी गुण होते हैं । इनमें से कई गुण होते है ।इन मे से कई गुण किसी राष्ट्रीयता में मिलते हैं, किन्तु इन सभी गुणों की उपलब्धता बहुत कम में होती है । ।

(2) **भाषा सम्बन्धी एकता** – धर्म के समान ही भाषा भी सामाजिक एकता का सर्वमान्य लक्षण है । अनेक राजनीतिक विद्वान किसी राष्ट्र के उत्थान में वहाँ की एवं सुदृढ़ीकरण में एक भाषा के महत्व को स्वीकार करते हैं । ऐसा माना जाता है कि भाषायी किसी राष्ट्र की एकता में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करती है । किन्तु यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि अनेक राज्यों में एक ही भाषा बोले जाने के बावजूद वे भिन्न–भिन्न राज्यों में हैं, जबकि कुछ राज्यों में अनेक भाषायें बोली जाती हैं, फिर भी वे सुदृढ़ व दीर्घकालिक राज्य हैं । सरकारी नीतियों को लागू करने और' प्रशासन के भली–भाँति संचालन में भाषायी विविधता राज्यों से अधिक असुविधा महसूस की जाती है । भाषायी विवाद के कारण अनेक राज्यों में घरेलू झगड़े होते हैं, जिन्हें सुलझाने में राज्यों की अपार शक्ति का हास होता है ।

(3) **धर्म सम्बन्धी एकता** – वर्तमान में यद्यपि धर्म बड़े–बड़े राज्यों अथवा साम्यवादी राज्यों में राष्ट्रीय एकता का तथ्य नहीं रहा है । धर्म अभी भी एकता अथवा विभाजन का कारण केवल कुछ राज्यों में ही बना हुआ है । यूगोस्लाविया राज्य के विभाजन के आर्थोडोक्स तथा कैथोलिक धर्मावलम्बियों का विभाजन ही मुख्य कारण था, इसी प्रकार धर्म ही भारत के विभाजन का भी आधार रहा । किन्तु ऐसा भी नहीं माना जा सकता है कि धर्म किसी 'राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधकर रहता है, उदाहरणार्थ पाकिस्तान का विभाजन इस्लाम राजधर्म होने के बावजूद नहीं रूक सका और पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश का निर्माण हो गया' । प्रारम्भिक अवस्था में धर्म ने सभी राज्यों को सुदृढ़, विकसित, विशाल और सबल संस्कृति प्रदान की । थी, किन्तु वर्तमान में इसे आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है ।

(4) **भौगोलिक. समरूपता** – आवश्यक नहीं है कि एक ही धर्म मानने वाले और एक ही भाषा बोलने वाले लोग किसी क्षेत्र में निवास करते हों तो वे एक राष्ट्र के! रूप में होंगे । इसका सबसे अच्छा एवं उपयुक्त समाधान भौगोलिक समरूपता अथवा संलग्नता के रूप मैं हो सकता है । व्यक्तियों के समूह का मिलकर एक सामान्य भूभाग पर रहना राष्ट्र के के लिए आवश्यक है । इस संदर्भ में कोहेन का विचार है कि 'जिस भूभाग पर लोग पैदा होते तथा वहाँ पर निवास करते हैं, उसे वे अपना निवास मानते हैं । एक समान वातावरण में एक साथ मिलकर रहने, समान भू–भाग तथा उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग करने का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण राष्ट्र प्रेम की भावना का जन्म होता है तथा राष्ट्र का ' रूप में विकास होता है।

विभाजन के परिणामस्वरूप कभी–कभी भौगोलिक संलग्नता नष्ट हो जाती है तथा प्राकृतिक संसाधन भी विभक्त हो जाते हैं, जिससे राष्ट्र शक्ति विच्छिन्न हो जाती है

(5) **सामान्य आर्थिक सम्बन्ध** – वर्तमान में राष्ट्र निर्माण में सामान्य, आर्थिक सम्बन्ध बड़े सहयोगी तथ्य के रूप में स्वीकार किये जाते हैं । आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में इसकी आवश्यकता और भी अधिक महसूस की जाती है । आज सभी राज्यों का मुख्य ध्येय यही रहता है कि बाह्य साधनों का त्याग कर स्वयं द्वारा आत्म निर्भरता प्राप्त की जा सके, किन्तु इसकी पूर्ण सफलता की आशा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है । राज्य के संसाधनों' का अधिकाधिक विकास प्रादेशिक एकता को सुदृढ़ता प्रदान करता है तथा वर्तमान । राज्य की प्राथमिक आवश्यकताऐं राजनैतिक स्वतंत्रता. व आर्थिक आत्म निर्भरता है । कोई भी राज्य केवल अपने संसाधनों के बूते पर अपनी जनसंख्या की समस्त आवश्यकताऐं पूर्ण करने में सक्षम नहीं है । अत: प्रत्येक राज्य का प्रयास यही है कि अपने उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हुए समर्थ राज्यों से सामान्य आर्थिक सम्बन्ध सुचारू बनाये रख सके ।

(6) **ऐतिहासिक. सामाजिक –सांस्कृतिक एकता** – परम्पराऐं, रीति– रिवाज, संस्कृति, त्यौहार वेश–भूषा, खान–पान, रहन–सहन आदि तथ्य भी कुछ मात्रा में राष्ट्रीय एकता के लिए सहायक होते हैं । ये सभी तथ्य किसी क्षेत्र विशेष की भिन्नता को विशिष्टता प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से एक सीमा तक क्षेत्रवाद का विकास भी होता है । वर्तमान राजनीति की क्षेत्रवाद भी विशिष्ट देन है । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि जब–जब भी शक्तिशाली अथवा श्रेष्ठ राज्य ने दूसरे निर्बल राज्यों पर अपनी सभ्यता और संस्कृति को अध्यारोपित करना चाहा है, तब उप–राष्ट्र वर्ग ने इसका घोर विरोध किया है ।

**बोध प्रश्न** – 2

1. ड्यूट्ज ने समयबद्ध रूप में राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र के विकास को किस रूप में व्यक्त किया है।

   …….

2. मिनोगू ने कितने प्रकार की राष्ट्रीयता बतायी है

   …….

3. राज्य एवं राष्ट्र समान है अथवा नहीं ।

   …….

4. राष्ट्र के किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखो ।

   …….

## 5.4 राष्ट्र –राज्य (NATIONAL National State)

पाउण्ड्स के अनुसार 'एक राज्य में अधिकतम एकता और स्थायित्व तब ही संभव है, जबकि वह एक राष्ट्र के साथ समानता रखता हो । ' ('A State is likely

to show the greatest stability and permanence when it corresponds closely with a National'.–Pounds) इस प्रकार राज्य की शक्ति समान राष्ट्रीयता में निहित है, विविध राष्ट्रीयता वाला राज्य निर्बल हो जाता है । वर्तमान एवं आधुनिक राज्यों में ही राष्ट्र – राज्य का विचार विकसित हो सका है, जो कि सभी राज्यों में नहीं हुआ है । विश्व के अनेक देश बहुराष्ट्रीय राज्य (Multinational State) हैं । बहुराष्ट्रवाद का कारण जातीय विविधता होती है । राष्ट्र एवं राज्य एक न होकर भिन्न–भिन्न होते हैं और साथ ही पूरक भी । जिन राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होता है, उनकी तुलना में राष्ट्रीयता पर आधारित राज्य प्रगतिशील एवं सुदृढ़ होते हैं । राष्ट्र–राज्य वहाँ विद्यमान होता. है, जहाँ राष्ट्र व राज्य में एकरूपता होती है । राजनीतिक क्षेत्र संगठन के आदर्श स्वरूप को राजनीतिक भूगोलवेता राष्ट्र–राज्य के रूप में इंगित करते हैं, क्योंकि राज्य राष्ट्र की अभिव्यक्ति है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता सुरक्षित रखी जाती है । राष्ट्र–राज्य वर्तमान समय का आधुनिक लक्षण है ।

रीति– रिवाज, भाषा, धर्म आदि की एकता से निर्मित राष्ट्र स्वाभाविक विकास के लम्बे काल का परिणाम है । सर्वशक्तिमान राज्य की विचारधारा को एक बार जब स्वीकार कर लिया गया, तो राष्ट्र और राज्य के मध्य एकरूपता लाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ और एक राष्ट्रीयता के लोगों के अधिकार का क्षेत्र ही राज्य क्षेत्र बन गया । राष्ट्रीयता में सैद्धान्तिक दृष्टि से कुछ भी अप्रमाणिक और गलत नहीं हैं, इसी कारण जॉन स्टुअर्ट, मिल, कार्ल मार्क्स, वुडरो विल्सन आदि ने राष्ट्र–राज्य का समर्थन किया था । सांस्कृतिक एकता का अनेक नवोदित राज्यों में अभाव है, तो भी वे राज्य बने हुए हैं और वहाँ पर सभी प्रकार के विघटनकारी तत्वों को दृढ़तापूर्वक अथवा बाहरी सहायता के द्वारा नियंत्रित रखा जाता है ।

अत: कहा जा सकता है कि एक ऐसी राजनीतिक इकाई जिसका क्षेत्र सीमांकित किया हुआ हो, अधिक एवं कुशल जनसंख्या से निवासित हो, शक्ति प्राप्त करने हेतु पूर्ण रूपेण संगठित हो तथा वहीं के लोग भावनात्मक एवं अन्य बन्धनों के कारण राष्ट्र को स्वयं । का समझते हों, इस प्रकार के बन्धन सरकार व कानून के रूप में अभिव्यक्त एवं स्वीकार किये जाते हों, ऐसी राजनीतिक इकाई को आदर्श राष्ट्र–राज्य की संज्ञा दी जा सकती है । सभी राज्य अपनी इकाईयों में शासन की भिन्न–भिन्न पद्धतियाँ प्रयुक्त करते हुए सुव्यवस्था का प्रयत्न करते हैं, तथा क्षेत्रीय, भाषायी, जातीय, धार्मिक मतभेद, आर्थिक भिन्न आदि विघटनकारी तत्वों को । नियंत्रण में रखते हैं, – किन्तु फिर भी कहा जा सकता है कि सभी राज्य इस ध्येय की प्राप्ति नहीं कर सके हैं। आधुनिक . युग का राष्ट्र–राज्य एक आदर्श है तथा ब्लिज इसे एक अस्थायी लक्षण हैं, किन्तु व्यक्तिगत अधिकारों के अधिक संरक्षण, निरंकुशता की समाप्ति, समूहों के

पारस्परिक और पिछड़े लोगों के समूह के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए इसे सभ्य अस्तित्व की चरम। आवश्यकता के रुप में माना जाता है ।

**बोध प्रश्न** –3

1. राज्य की शक्ति किसमें निहित होती है।

   …….

2. विविध राष्ट्रियता वाला राज्य बाद मे कैसा हो जाता है।

   ……

3. राष्ट्रियता पर आधारित राज्य किस प्रकार के होते है ।

   …….

4. राष्ट्र - राज्य का समर्थन किन लोगो ने किया।

   ……..

## 5.5 सारांश (Summary)

राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं द्वारा राज्य ' को एक जीवित इकाई के रूप। में अभिव्यक्त किया । है, जिसे उपयुक्त भौगोलिक वातावरण की प्राप्ति होती है तो वे अपने क्षेत्र का । विस्तार करता रहता है । राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में राज्य का स्थान सर्वोच्च है । जैसे–जेसे राज्य मैं रहने वाले उसके नागरिकों में राजनीतिक परिपक्वता में वृद्धि होती जाती है, वैसे–वैसे उनकी अपने राज्य के प्रति राजनीतिक आस्था भी बढ़ती जाती है, और अन्ततः इसी के कारण राष्ट्र ' का निर्माण प्रारम्भ हो जाता है ।

भौगोलिक इकाई के रूप में तीन तत्वों क्षेत्र, मानव एवं राजनीतिक ' को सम्मिलित । किया जाता है, ये तीनों तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में नहीं होकर प्रत्येक का अस्तित्व एक–दूसरे पर निर्भर है । विद्वानों में राष्ट्र के निर्धारक तत्वों के सम्बन्ध में मैतैक्य नहीं है । कुछ भाषा को, तो कुछ धर्म को, तो अन्य प्रजाति को अधिक महता प्रदान करते है । । राष्ट्र में सांस्कृतिक एकत्व एवं भावना की प्रधानता होती है । जब राष्ट्र के निवासियों द्वारा अपनी सरकार को जो उनके स्वयं के लोगों द्वारा परिचालित हो, को महत्व देना प्रारम्म कर दिया जाता, तो उस राज्य का प्रत्येक नागरिक अपने आपको उस राज्य का अंग मानते हुए गौरव का करता है, उस स्थिति में राष्ट्र–राज्य ' का विकास प्रारम्भ हो जाता है ।

## 5.6 शब्दावली (Glossary)

राजनीतिक भूगोल - भूगोल की ऐसी शाखा जिसमें भौगोलिक संदर्भ में राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाये ।

राज्य - राज्य को राजनीतिक भूगोल में एक जीवित इकाई के रूप में प्रतिपादित किया है ।

केन्द्रीय स्थल - राज्य का ऐसा हृदय स्थल जहाँ से सैनिक. राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के संचालन का केन्द्र हो ।

सीमान्त प्रदेश - किसी राज्य की सीमाओं के समीप का भाग ।

क्रमिक विकास - धीरे–धीरे विकास होने की प्रक्रिया ।

सघन बसे क्षेत्र - जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक हो

लोक कल्याणकारी - लोगों की भलाई के लिए किये जाने वाले प्रयास

निरंकुशता - तानाशाही

नियंत्रण - अधिकार

प्रभुसत्ता - स्वयं का शासन, किसी की पराधीनता नहीं, पूर्णरूपेण स्वतंत्र

परिवहन के साधन - यातायात/आवागमन के साधन

वृहत् - बड़ा

धर्मावलम्बी - धर्म को मानने वाले

## 5.7 संदर्भ ग्रन्थ


1. सक्सैना, हरिमोहन - World Political Patterns ,John Murray ,London,1996

2. भट्टाचार्य एवं अच्छा - Systematic Political Geography,John Wiley,1993

3. Alexander,L.M. - Geography and Political in a Divided World Methuen London 1964

4. Blij,H.J.de - Poltical Geography ,Tata McGraw Hill ,New Delhi

5. Cohen ,S.B - Geography and Political in a Divided World Methuen London 1964

6. Dikshit R.D - Politica Geography ,Tata McGraw Hill ,New Delhi

7. Moodie A.E - Geography Behind Political ,Hutchinson University Library ,London 1963

8. Pounds,N.J.G - Political Geography ,McGraw Hill,1963

9. Valkenbarg,S.V & Stoz C.L. - Elements of Political Geography prentice Hall of India ,New Delhi,196


## 5.8 बोध प्रश्नों के उतर

**बोध प्रश्न** – 1

1. जीवित इकाई के रूप में ।
2. हार्टशोर्न व्हिटलसी जोन्स, मूडी, पाउण्ड्स ।
3. टयूटोनिक भाषा से ।
4. क्षेत्र, मानव एवं राजनीतिक संगठन ।
5. प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल ।
6. जनसंख्या, भूभाग, सरकार, प्रभुसत्ता, आर्थिक स्वरूप, संचार एव परिवहन ।

**बोध प्रश्न** – 2

1. समाज समुदाय जनसमुदाय राष्ट्रीयता राष्ट्र ।
2. छः प्रकार की ।
3. राज्य एवं राष्ट्र समान नहीं है ।
4. प्रजाति एवं रक्त की एकता, भाषा सम्बन्धी एकता, धर्म सम्बन्धी एकता, भौगोलिक समरूपता आदि ।

**बोध प्रश्न** – 3

1. समान राष्ट्रीयता में ।
2. वह राज्य निर्बल हो जाता है ।
3. प्रगतिशील एवं सुदृढ़ होते हैं ।
3. जॉन स्टुअर्ट, मिल, कार्ल मार्क्स, वुडरो विल्सन आदि ।

## 59. अभ्यासार्थ प्रश्न

1. राजनीतिक प्रदेश किसे कहते हैं तथा इसकी विशेषताऐं क्या है,?
2. भौगोलिक संदर्भ में राज्य की व्याख्या करते हुए उसके भौगोलिक ' लक्षणों पर प्रकाश डालिये ।
3. राज्य के तत्वों पर एक लेख लिखिये ।
4. राज्यों की विकास प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिये ।
5. राज्यों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत कीजिये ।
6. राष्ट्र को परिभाषित करते हुए इसके आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिये ।
7. राष्ट्र–राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं?
8. राज्य एवं राष्ट्र में अंतर स्पष्ट कीजिये तथा राष्ट्र–राज्य के महत्व को समझाइये ।